

ए०एल० बनर्जी,
आई.पी.एस.



पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
१-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 13.2014

विषय- क्रिमिनल अपील संख्या-1277/2014 अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.7.2014 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रिय महोदय/महोदया,

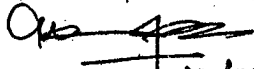
कृपया उपर्युक्त विषयक मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.07.2014 के अनुपालन में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या:3/5/2008-Judl.Cell दिनांक:10.07.2014 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करे। प्रश्नगत प्रकरण में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्यतः निम्न निर्देश दिये हैं:-

- (1) सभी राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करें कि जब भी कोई अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए भादंवि के अधीन पंजीकृत हो तो उससे सम्बन्धित अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले धारा 41 दं०प्र०सं० के दायरे के अन्तर्गत गिरफ्तारी की आवश्यकता पर स्वयं सन्तुष्ट हो लें।
- (2) सभी पुलिस अधिकारीगण को चेक लिस्ट प्रदान की जाए, जिनमें धारा 41(1)(b)(ii) की उपधारा का वर्णन हो।
- (3) गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष निरूद्ध किये जाने की संस्तुति से पूर्व ऐसे पुलिस अधिकारी को इन चेक लिस्ट में बाकायदा प्रविष्टि करना चाहिए और उसमें ऐसी गिरफ्तारी के औचित्य के बारे में विवरण अंकित किया जाना चाहिए।
- (4) मजिस्ट्रेट को चाहिए कि अभियुक्त को न्यायालय हिरासत में लिए जाते समय सम्बन्धित पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट का अनुश्रवण किया जाना चाहिए तथा ऐसे अभियुक्त को निरूद्ध किये जाने से पहले अपनी संस्तुति को लिपिबद्ध किया जाना चाहिए।
- (5) अभियुक्त की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में पंजीकरण होने के दो सप्ताह के अन्दर एक प्रति मजिस्ट्रेट को एवं एक प्रति जनपदीय पुलिस अधीक्षक के पास प्रेषित की जाये, जिसमें गिरफ्तारी न किए जाने के सम्बन्ध में कारणों का वर्णन हो।
- (6) धारा 41ए दं०प्र०सं० के अनुपालन के सम्बन्ध में अभियुक्त को उपस्थित होने हेतु नोटिस को अभियोग पंजीकरण के दो सप्ताह के भीतर को तामील करायी जाय, जिसकी समय सीमा जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कारण अंकित करते हुए बढ़ायी जा सकती है।

(7) उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी विभागीय कार्यवाही के अलावा सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अवमानना के दण्ड के भी प्रतिभागी होंगे।

(8) बिना कारण लिपिबद्ध किये निरूद्ध आदेश जारी करने पर सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के निरूद्ध विभागीय कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश का अनुपालन प्रभावी तरीके से करना/कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

 (ए०एल० बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
 प्रभारी जनपद(नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 2.अपर पुलिस महानिदेशक, सी०बी०सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ।
- 3.अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- 4.पुलिस महानिरीक्षक, समस्त जोन, उ०प्र०।
- 5.पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उ०प्र०।

25662/6-5-3-14

No. 3/5/2008-Judl.Cell
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

4th Floor, C Wing, NDCC-II Building
Jai Singh Road
New Delhi -110 001.
Dated: July 10, 2014

16/7/2014
(आलोक रजन)
मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन

25662/MS/GI/2014

ft-1

To
All Chief Secretaries of State Government/Union Territories Administrations.
(As per listed attached)

Subject: Advisory on measures to be taken by the States/UTs to curb the misuse of section 498-A of the Indian Penal Code- regarding.

Sir/ Madam,

The Government has, from time to time, issued advisories on measures to be taken by the States/UTs to curb the misuse of section 498-A of the Indian Penal Code.

2. On 02.07.2014 the Hon'ble Supreme Court, in the case of Arnesh Kumar Vs State of Bihar and Anr. (copy enclosed), observed that there is a phenomenal increase in matrimonial disputes in recent years and the fact that section 498-A is a cognizable and non bailable offence has lent it a dubious place of pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shields by disgruntled wives. The Hon'ble Supreme Court has observed the following:

i) All the State Governments to instruct their police officers not to automatically arrest a person when a case under Section 498-A of the IPC is registered but to satisfy themselves about the necessity for arrest under the parameters laid down flowing from Section 41, Cr.PC;

ii) All police officers be provided with a check list containing specified sub-clauses under Section 41(1)(b)(ii);

police officer shall forward the check list duly filled up and furnish the reasons and materials which necessitated the arrest, while producing the accused before the Magistrate for further detention;

Magistrate, while authorising detention of the accused, shall peruse the report furnished by the police officer along the terms aforesaid and only after recording its satisfaction, the Magistrate will authorise detention;

7119
DSC(L)

(डा० सरोज कुमार)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

contd.

विशेष सचिव (चर्चा हट्ट)
युक्तक P-3 में
व्यवहृत विधि जाना चाहिए।

575K
तत्काल चर्चा
30-7-14
(एस० के० रघुवंशी)
सचिव,
गृह विभाग,
उ० प्र० शासन

959/SHR/2014

सोप-3
31/7/14
Rc/R
31/8/14

v) The decision not to arrest an accused, be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate which may be extended by the Superintendent of Police of the district for the reasons to be recorded in writing;

vi) Notice of appearance in terms of Section 41A of Cr.PC be served on the accused within two weeks from the date of institution of the case, which may be extended by the Superintendent of Police of the District for the reasons to be recorded in writing;

vii) Failure to comply with the directions aforesaid shall, apart from rendering the police officers concerned liable for departmental action, also make the officers liable to be punished for contempt of court to be instituted before the High Court having territorial jurisdiction;


viii) The Judicial Magistrate concerned shall be liable for departmental action by the appropriate High Court if he authorizes detention without recording the reasons, as aforesaid.

3. The Hon'ble Court has directed that a copy of the judgment should be forwarded to the Chief Secretaries as also the Directors General of Police of all the State Governments and the Union Territories and the Registrar General of all the High Courts for onward transmission and ensuring its compliance.

4. All the State Governments/UT Administrations are requested to take effective measures to scrupulously enforce the directions/order of the Hon'ble Supreme Court as also the advisories issued by the Government of India from time to time.

5. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,



10/7/2014

(J.P. Agrawal)

Joint Secretary (Judicial)

Ph No. 23438113

Enclosed as above